THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). Government have seen the relevant news report. Facts are being ascertained.

राज्यों और गांवों में टेलीविजन सेट्स लगाने के लिए मानदण्ड

5672. श्री विभूति मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और ग्रामों में टेलीविजन लगाने के लिए क्या मानदण्ड बनाया गया है ;

(ख) क्या 28 फरवरी, 1975 तक बहुत से राज्यों और ग्रामो की सूची में सम्मिलित नही किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रो के लिए एक समान नीति अपनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन उपग्रह संचार टेलिविजन प्रयोग के लिए 6 क्षेत्रो के ग्रामो मे 2400 सीधे रिसैप्शन सैट लगाने के काम में लगी हुई है इन ग्रामो के चुनाव का मुख्य मापदण्ड बिजली की उपलब्धता, भाषाई निकटता, इत्यादि थे ।

दिल्ली, श्रीनगर तथा बम्बई के वर्तमान टेलीविजन केन्द्रो के सेवाक्षेत्रो के अन्दर भी कुछ सामान्य सामुदायिक टेलीविजन सैट लगाए गए हैं । सामुदायिक टेलीविजन योजना के अन्तर्गत निकट भविष्य मे चालू होने वाले हैं, केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों के अन्दर और टेलीविजन सैट लगाने का ख्याल है ।

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन के प्रभाव तथा उसकी उपयोगिता बढाने के माध्यम के रूप में सामुदायिक टेलीविजन योजना पर बहुत जोर देती है, परन्तु केन्द्र तथा राज्यो के पास उपलब्ध सीमित धनराशि के कारण इसका आकार सीमित है

दामोदर घाटी निगम के अधीन चल रहे मिडल और हाई स्कूल

5673. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अधीन पंचेत, कोनार, तिलैया और दुर्गापुर मे मिडल और हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं ;

(ख) क्या पंचेत मिडल इंगलिश स्कूल को छोड कर मिडल स्कूल कोनार, मिडल और हाई स्कूल तिलैया तथा मिडल और हाई स्कूल दुर्गापुर मे उर्दू भाषी छात्रो को पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षको की नियुक्ति नही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निगम के स्कूलों में जो स्नातकोत्तर शिक्षक, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि पढाते हैं उन्हे सीनियर स्केल दिया जाता है और उर्दू शिक्षकों को जूनियर स्केल दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव की नीति के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम पंचेत और तिलैया में मिडिल और

हाई स्कूल चलाना है । दुर्गापुर में केवल हाई स्कूल है तथा कानार में केवल मिडिल स्कूल है ।

(ख) पंचेत के मिडिल और हायर सेकण्डरी-दोनों स्कूलों में उर्दू के अध्यापक हैं । कानार के मिडिल स्कूल में भी उर्दू जानने वाला एक अध्यापक है । तिलया और दुर्गापुर के स्कूलों में उर्दू के अध्यापकों की कोई मांग नहीं है ।

(ग) जहां-कहीं आवश्यकता है वहां निगम द्वारा उर्दू के अध्यापक नियुक्त किए गए हैं ।

(घ) बिहार और पश्चिमी बंगाल में हायर सेकण्डरी प्रणाली की समाप्ति से पहले नियुक्त भाषा अध्यापकों को वेतन का उच्च वेतनमान निरन्तर दिया जा रहा है । हायर सेकण्डरी प्रणाली की समाप्ति के बाद, तिलैया में उर्दू अध्यापकों और संस्कृत अध्यापक के पद स्नातक अध्यापक के वेतनमान में स्वीकृत किए गए हैं ।

(ङ) भेदभाव की कोई नीति नहीं बरती जा रही है ।

Collaboration proposals with Foreign Companies

5674. SHRI NOORUL HUDA:
SHRI RAJDEO SINGH:
SHRI N. E. HORO:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of collaboration proposals with foreign companies, approved by Central Government in 1974;

(b) how many proposals involve foreign equity participation and the amount involved; and

(c) the names of countries and the major firms (foreign) involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) The total number of foreign collaboration proposals approved by the Government of India during the year 1974 is 359.

(b) Out of 359 cases, fifty-four cases involved foreign equity participation totalling Rs. 669.34 lakhs.

(c) Quarterly statements of foreign collaboration proposals approved by the Government during the year 1974 indicating the name of the Indian party, the name and country of the foreign collaborator, the item of manufacture and whether the proposal also involves foreign capital participation, are available in the Parliament Library.

Use of Language in Assam

5675. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister had received, during the past one year, representations from linguistic minorities in Assam alleging compulsory introduction of the majority language on all linguistic minority students studying in Secondary Schools against their will and consent and further alleging discriminatory syllabus in the Schools affecting minority students;

(b) whether Union Government have ascertained facts from the State Government of Assam regarding the said allegations; and

(c) the steps taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) to (c). Representations have been received alleging compulsory introduction of the majority language in Secondary Schools of Assam and further alleging discriminatory